

प्रेषक

मनीषा पवार
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सवा में

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-1

देहरादून दिनांक // अगस्त, 2009

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभाग के मुख्यालय एवं मण्डीय अधिष्ठान हेतु अनुदान संख्या-15 के आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशियों के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 515/XXVII(1)/2009 दिनांक 28 जुलाई, 2009 की और आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभाग से संबंधित मुख्यालय एवं मण्डीय अधिष्ठान व्यय हेतु अनुदान संख्या-15 के आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशियों में से संलग्नता के अनुसार रुपये 87,60,000/- (रुपये सत्तासी लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि (01 अप्रैल, 2009 से 31 जुलाई, 2009 तक के लिए पारित लेखा अनुदान की धनराशि को सम्मिलित करते हुए) को चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 की अवशेष अग्रिम में वित्त विभाग के उक्त शासनादेश में उल्लेखित एवं निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवेदन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

1. विभागाध्यक्षों तथा अन्य नियंत्रक अधिकारियों के निस्तरण पर जो धनराशि रखी गयी है वह उनके द्वारा जनपद के अहरण-वितरण अधिकारियों को एक मसौदा के अन्तर तत्काल अग्रमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
2. वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 515/XXVII(1)/2009 दिनांक 28 जुलाई, 2009 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिश-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. आयोजनागत/आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित अन्य धनराशियों हेतु नियमानुसार मांग प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की प्रोजेग (त्रिमास के आन्तर पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए जिससे राज्य स्तर पर कैशपत्ती निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
5. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्य के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
6. यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय-व्ययक 2009-10 में बजट प्राविधान लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय-व्ययक प्राविधान की सोमा तक ही व्यय की जायगी।

7. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
8. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सन्पूर्ण मुख्य/तघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्वाही से अनुदान संख्या-15 तथा आयोजनोत्तर/आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
9. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर ले कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
10. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय-सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
12. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
13. समस्त बालू निर्माण कार्य, नए निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय, वाहन का क्रय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय की स्वीकृतियों के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को पृथक् से उपलब्ध कराए।
14. बी0एम0-13 पर संकलित मसिफ व्यय की सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
15. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रेस्पोजमेंट रूल 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड -1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम) आय-व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
16. यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
17. इस संवत् में होने वाला व्यय बालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-15 के अंतर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के माध्यम से होना चाहिए।
18. यह आदेश वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 515/XXVII(1)/2009 दिनांक 28 जुलाई, 2009 के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीया

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठकन संख्या: संख्या-789/XVII-1/2009-10(11) 2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1. निजी सचिव-मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-मा० समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊँ मण्डल उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कौषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त कौषाधिकारी उत्तराखण्ड।
10. वरिष्ठ कौषाधिकारी, हल्द्वानी, नैनीताल।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
12. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून।
13. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
- ✓ 15. आदेश पंजिका।

आज्ञा से

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।

अनुदान संख्या-15

आयोजनेत्तर

भतदेय

लेखशीर्षक

2225-01-001-03-00

मुख्य शीर्षक

2225-अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण।

उप मुख्य शीर्षक

01-अनुसूचित जातियों का कल्याण।

संघ शीर्षक

001-निर्देशन तथा प्रशासन।

उप शीर्षक

03- मुख्यालय एवं मण्डलीय आधिकारिक

व्यवहार शीर्षक

00-

(प्रतिशत हजार रुपये में)

मानक मद	आवृत्त धनराशि
01- वेतन	8000
02- मजदूरी	10
03- महगाई भत्ता	1500
06- अन्य भत्ता	900
09- विद्युत देय	75
13- टेलिफोन व्यय	75
15- गाड़ियों का अनुसूचित और पेट्रोल आदि की खरीद	75
17- किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	125
योग	8760

(रुपये सत्तासी लाख साठ हजार मात्र)

(भीरेन्द्र सिंह दत्ताल)
उप सचिव।